Kashmir Unit has been functioning in the Ministry of External Affairs for the past few decades. This Unit is entrusted with matters pertaining to J&K in our foreign policy concerns.

Commercial Intelligence Wings of Indian Missions Abroad

4620. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Government had assured in August 1993 that Indian missions abroad would help in collecting commercial information to assist Indian manufacturers in filing anti-dumping petitions;

(b) if so, whether despite this assurance there have been complaints from Indian manufacturers alleging that the Indian mission in the USA refused to entertain such requests seeking data on the prevailing US prices for chemicals; and

(c) whether Government would consider strengthening the commercial intelligence wings of Indian missions abroad, commensurate with the increasing volume of enquiries/requests for market data/information from Indian manufacturers in the wake of liberalised import policies ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : (a) to (c) No, Sir, no assurance has been provided by this Ministry. However, in discussions with the business community it has been suggested that if they face any problem in the area of dumping they could bring this to our attention and we will render whatever assistance we can.

The Ministry of Commerce deals with matters relating to anti-dumping and they will be developing the appropriate strategy to meet with the requirements of India.

In keeping with the higher importance attached to economic diplomacy, the commercial wings of our missions/posts abroad are increasingly providing trade and commercial information and data to concerned agencies/individuals in India and abroad.

पारपत्र पुस्तिकाओं की अनुपलब्धता

4621. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र पुस्तिकाओं की अनुपलब्धता के कारण पारपत्रों को जारी करने मे बिलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान पारपत्र पुस्तिकाओं की अनुपलब्धता के कारण पारपत्रों के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब का सिलसिला 1991 में शुरू हुआ था और 1992 के मध्य तक बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया जिसकी एक वजह पासपोर्ट बुकलेटों की सप्लाई में भारी कमी भी थी। इनकी सप्लाई में नवम्बर 1992 में वृद्धि होने लगी और अब माग को देखते हुए ये काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ग) बकाया काम के आंकडे इस तरह नहीं रखे जाते। तथापि नवम्बर 1992 के अन्त में लगभग 11.43 लाख ऐसे नये आवेदन थे जिन पर कार्रवाई पूरी होनी थी और नवम्बर, 1993 के अन्त में ऐसे आवेदनों की कुल संख्या 5.37 लाख थी।

नया पारपत्र जारी करने के लिए समय सीमा

4622. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि नया पारपत्र जारी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है;

(ख) यदि नही तो इस सम्बन्ध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है: